अपराधों और हत्याओं की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अपराध	हत्या
1988 .	34,443	296
1989 .	38,249	351
1.1.90 से 30.6.90 तक	62,037	636

हत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोत्तरी के प्रमुख कारण तेजी से हो रहे शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न आर्थिक हालात और सामाजिक तनाव है ।

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए कदमों में गस्त में बढ़ोत्तरी संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, सतर्कता में वृद्धि पडोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकों, ज्ञात अपराधियों के खिलाफ निष्कासन कार्रवाई करना इत्यादि शामिल है ।

Evaluation of the functioning of Mahanagar Telephone Nigam Limited in Delhi and Bombay

649. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have evaluated the functioning of Mahanagar Telephone Nigam Limited in Delhi and Bombay;

(b) if so, what are the findings;

(c) whether Government propose to establish similar Corporations for other major cities in the country; and

(d) if so, the details of the proposal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. The Quality of Telephone Service (QOTS) in Bombay and Delhi Telephone Systems under the Mahanagar Telephone Nigam Limited has been evaluated by an independent agency viz. the Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI).

(b) The findings are that there has been perceptible improvement in QOTS in Delhi and Bombay.

(c) There is no proposal under consideration of the Government at present to establish similar Corporation for other major cities in the country.

(d) Does not arise.

टेलीफोनों के लिए तीन श्रेणियों की प्रतीक्षा सूचियां

650. **डा० अबरार अहमद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान के जिला मुख्यालयों में टेलीफोनों के लिए तीन श्रेणियों अर्थात् सामान्य, ओ०वाई० टी० और माननीय मंत्री द्वारा बिना बारी के आधार पर मंजूर टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूचियों में कितने-कितने व्यक्ति हैं और प्रतीक्षा सूचियों की इन तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में टेलीफोन लगाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) निकट भविष्य में राजस्थान में किन-किन स्थानों पर नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है और उनकी क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है, जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) सरकार को अत्यधिक भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) आगामी तीन महीनों के दौरान राजस्थान के पुराने क्षेत्रों में 8 नये टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है। उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

स्थान	एक्सचेंज क्षमता
1. नीमराणा (अलवर जिला)	25 लाइनें
2. बन्गाक्षी (झुनझुनू जिला)	25 लाइनें
3. दुलानिया (झुनझुनू जिला)	25 लाइनें
4. चरौली (सीकर जिला)	25 लाइनें
5. सीवादुआरी (सीकर जिला)	25 लाइनें
6. गजसींघपुरा (जोधपुर जिला)	25 लाइनें
7. हरोड़ी (सवाई माधोपुर जिला)	25 लाइनें
8. जमुआं रामगढ़ (जयपुर जिला)	128 लाइनें

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	ओवाईटी	प्रतीक्षा सूची गैर-ओवाईटी	बिना बारी के टेलीफोन के लिए प्राप्त मंजूरियों की संख्या।
1	2	3	4	5
1	अजमेर . . .	367	3778	19
2	अलवर . . .	108	2384	14
3	बारां . . .	1	231	1
4	बांसवाड़ा . . .	..	..	..
5	डूंगरपुर . . .	41	938	2
6	बाड़मेर . . .	7	212	3
7	भरतपुर . . .	10	1041	—
8	भीलवाड़ा . . .	253	3110	5
9	बीकानेर . . .	243	3566	34
10	बून्दी . . .	66	244	—
11	चित्तौड़गढ़ . . .	35	190	—
12	चुरू . . .	7	137	—
13	दौसा . . .	4	188	—
14	धौलपुर . . .	3	66	—

1	2	3	4	5
15	जयपुर	1642	41837	566
16	जैसलमेर . . .	14	116	2
17	जालौर . . .	5	153	—
18	झालावाड़ . . .	4	94	1
19	झुनझुनु	8	380	9
20	जोधपुर . . .	464	11150	31
21	कोटा	374	5963	18
22	नागोर	17	303	4
23	रायत	22	1034	—
24	राजसमन्द . . .	33	387	—
25	सवाई माधोपुर . . .	—	102	1
26	सीकर	32	131	—
27	सिरोही . . .	53	179	—
28	श्री गंगानगर . . .	299	2109	3
29	टोंक	14	201	4
30	उदयपुर	624	8804	25

प्रतीक्षा सूची के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान किये जा रहे है ।

भारतीय यार्डों में जहाज की मरम्मत की सुविधा

651. **श्री रणजीत सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1991 के फाईनेंसियल एक्स-प्रेस में "शिप रिपेयर फेसिलिटीज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जहाज-मालिकों ने भारतीय यार्डों में जहाजों की समय तथा धन की दृष्टि से मंहगी मरम्मत होने की शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतों की जांच की है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मरम्मत कार्य करने वाले इन यार्डों में सुधार करने के लिए हाल ही में कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो हाल ही में अन्य क्या-क्या सुधार किए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।